U.P. SUGAR MILLS ASSOCIATION

403,Chintels House
16, Station Road
Lucknow-226001

Ref No.

Dated 01-12-2013

To,

The Chief Minister,
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Subject : Start of crushing operations by the sugar mills for the season 2013-14.

Respected Sir,

The industry is passing through a very difficult phase due to very high cane price for the season 2013-14. Considering the interest of the farmers and the viability of the industry, we are willing to start the crushing operation with immediate effect if the following genuine demands of the industry are agreed upon by the government :-

(1) Industry acknowledges that the interest of farmers is paramount and they must get the most remunerative prices for their produce. However, cane price must also be determined in such a manner that the long term viability of the sugar industry is ensured. It is imperative that a transparent mechanism be developed for the determination of cane price that looks after the interests of both the farmers and the sugar mills. It is urged that a committee under the chairmanship of Chief Secretary be constituted to evolve a long term mechanism for the fair determination of sugarcane price while looking at all

possible methods including the recommendations made in the Rangarajan Committee report. The committee should give its report within three months.

(2) As the government has declared the SAP of Rs. 280/ quintal for the season 2013-14, the industry agrees to pay the farmers this price and it will stamp the supply tickets/'purchis' with the rate of Rs. 280 per quintal. The payment to the farmers will be in two installments. The first installment will be of Rs. 260 per quintal which will be paid expeditously while the second installment will be of Rs. 20 per quintal to be paid latest by the end of the season.

(3) In view of the extremely low sugar price, the government shall give the following concessions with immediate effect for the season 2013-14 :-

a) Waiver of entry tax on sugar - Rs. 2.73/ quintal
b) Waiver of purchase tax - Rs. 2.00/ quintal
c) Society commission - Rs. 6.30/ quintal

Total - Rs. 11.03/ quintal

(4) The balance amount of Rs. 8.97 (Rs. 20.00 – Rs. 11.03 (concession/waiver)) will be paid by the sugar industry and/or the government. The sharing mechanism would be determined by a committee under the chairmanship of Agriculture Production Commissioner. This committee will hear the views of the sugar industry and seek help of outside professional experts to determine the paying capacity. If the prices of sugar fall below a level determined by the committee, then the entire amount

(3)

of Rs. 8.97/ qtls. will be borne by the government. If the prices of sugar rise above a level determined by the committee, then the industry will bear the entire burden of the balance amount. For sugar prices between these two levels, the balance amount of Rs. 8.97/quintal would be shared between the sugar industry and government in accordance with a formula determined by the committee. The committee will give its report within three months.

We hope and trust that our above suggestions will be accepted expeditiously by government to resolve the present crisis in the sugar sector.

Thanking You,

Yours faithfully
For U.P. Sugar Mills Association

Secretary

प्रेस विज्ञप्ति

उ0प्र0 शासन की पहल पर चीनी मिलों में पेराई प्रारम्भ

असमंजस की स्थिति समाप्त

लखनऊ : दि0 01 दिसम्बर, 2013

चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश के लिये सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है। लगभग 32 लाख से अधिक कृषक परिवार तथा 02 लाख से अधिक श्रमिक परिवार इस उद्योग के साथ सीधे जुड़े हैं। प्रदेश में 123 चीनी मिलें कार्यरत् हैं और एक पेराई सत्र में लगभग 22500 करोड़ रुपये गन्ने के मूल्य के रूप में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेशित होता है।

प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में गन्ने की अहम भूमिका को पूरी तरह समझती है। इस सम्बन्ध में गन्ना मूल्य निर्धारण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रदेश सरकार कटिबद्ध है कि गन्ना मूल्य ऐसे स्तर पर निर्धारित किया जाये जिससे जहाँ एक तरफ गन्ना कृषकों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके, वहीं दूसरी ओर चीनी मिलों की सम्पोषकीयता (Viability) बनी रहे। इन सभी पहलुओं तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पिछले कुछ महीनों में चीनी की कीमतों में बहुत अधिक गिरावट आयी है, राज्य सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र में गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) को गत् वर्ष के समतुल्य यथा रुपये 280 प्रति कुंतल रखा है।

चीनी मिलों ने रुपये 280 प्रति कुंतल की उपर्युक्त दर को नहीं माना था और पेराई प्रारम्भ नहीं की थी। उनकी मांग थी कि गन्ने की दर रुपये 225 प्रति कुंतल रखी जाये, किन्तु सरकार ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया था। साथ ही सरकार ने चीनी मिलों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया और कड़ाई से चीनी मिलों को निर्देशित किया गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विलम्बतम् 04 दिसम्बर, 2013 तक और प्रदेश के शेष भाग में 07 दिसम्बर, 2013 तक पेराई प्रारम्भ की जाये।

सरकार के द्वारा किसानों के हित में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन ने दिनांक 01.12.2013 को भेजे गये अपने पत्र में यह सूचित किया है कि वह तत्काल प्रभाव से गन्ने की पेराई प्रारम्भ करेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि उनके द्वारा प्रदेश की समस्त निजी चीनी मिलों को अविलम्ब पेराई करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन द्वारा यह भी लिखकर दिया गया कि वह शासन द्वारा घोषित राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) रुपये 280 प्रति कुंतल स्वीकार करते हैं तथा पर्ची पर रुपये 280 प्रति कुंतल मूल्य ही अंकित करेंगे। किन्तु चीनी के दामों में हुई भारी कमी को दृष्टिगत् रखते हुए उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि वह किसान को तत्काल रुपये 260 प्रति कुंतल का मूल्य अदा करेंगे और अवशेष रुपये 20 प्रति कुंतल विलम्बतम् पेराई सत्र के अन्त तक अदा कर देंगे। किसान के हित में तत्काल गन्ना पेराई प्रारम्भ करने की आवश्यकता तथा पेराई में होने वाले विलम्ब के कारण किसान को होने वाली हानि को दृष्टिगत् रखते हुए शासन द्वारा चीनी मिलों का उपरोक्त अनुरोध मान

लिया गया। इसके फलस्वरूप, अविलम्ब चीनी मिलों में पेराई प्रारम्भ हो जाएगी।

चीनी मिल एसोसिएशन द्वारा यह भी अनुरोध किया गया कि चीनी के दामों में हुई भारी कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार द्वारा चीनी पर प्रवेश–कर तथा गन्ने पर क्रय–कर माफ किया जाये। साथ ही उन्होंने यह अनुरोध किया कि इस वर्ष गन्ना समितियों को देय कमीशन राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाये। चीनी के दाम में हुई कमी के कारण चीनी मिलों के समक्ष उत्पन्न वास्तविक कठिनाइयों को दृष्टिगत् रखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन के उपरोक्त अनुरोध को स्वीकार किया।

शासन द्वारा सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह तत्काल अपने जनपद की चीनी मिलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके यह सुनिश्चित करायें कि अविलम्ब सभी चीनी मिलों में पेराई प्रारम्भ हो जाये।